

आदर्श आचार संहिता

प्रलिस के लयि:

[आदर्श आचार संहिता, जन परतनिधितिव अधनियिम, 1951, चुनावी बाँणड,](#)

मेन्स के लयि:

आदर्श आचार संहिता का वकिस, चुनावों में MCC का महत्त्व और आलोचनाएँ। चुनावी प्रथाएँ, चुनावी सुधार, MCC के माध्यम से लोकतंत्र सुनश्चिति करना, चुनावी फंडगि

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारत नरिवाचन आयोग](#) द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लयि मतदान की तारीखों की घोषणा के साथ [आदर्श आचार संहिता](#) (MCC) लागू हो गई है, जो चुनावी शासन के एक महत्त्वपूर्ण पहलू को चहिनति करती है।

MCC क्या है और इसका वकिस क्या है?

परचिय:

- MCC एक **सर्वसम्मत दस्तावेज** है। राजनीतिक दल स्वयं चुनाव के दौरान अपने आचरण को नयितरति रखने और संहिता के भीतर काम करने पर सहमत हुए हैं।
- यह चुनाव आयोग को संवधान के **अनुच्छेद 324** के तहत दयि गए **जनादेश** को ध्यान में रखते हुए मदद करता है, जो उसे संसद और राज्य वधानमंडलों के लयि **संवतंत्र तथा नषिपकष चुनावों** की नगिरानी एवं संचालन करने की शकृता देता है।
- **MCC चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से परणाम की घोषणा की तारीख तक चालू रहता है।**
- संहिता लागू रहने के दौरान सरकार कसिी वतितीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकती, सड़कों या अन्य सुवधियों के नरिमाण का वादा नहीं कर सकती और न ही सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम में कोई तदर्थ नयिकृत्तिकर सकती है।

MCC की प्रवर्तनीयता:

- हालाँकि **MCC के पास कोई वैधानिक समर्थन नहीं** है, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा इसके सख्त कार्यान्वयन के कारण पछिले दशक में इसे ताकत मली है।
 - MCC के कुछ प्रावधानों को [भारतीय दंड संहिता 1860](#), [दंड प्रकरयि संहिता 1973](#) और [जन परतनिधितिव अधनियिम 1951](#) जैसे अन्य कानूनों में संबधति प्रावधानों को लागू करके लागू कयिा जा सकता है।

MCC का वकिस:

- **केरल चुनाव के लयि आचार संहिता अपनाने वाला पहला राज्य** था। वर्ष 1960 में राज्य में वधान सभा चुनावों से पहले, प्रशासन ने जुलूस, राजनीतिक रैलयियों और भाषणों जैसे चुनाव प्रचार के महत्त्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करते हुए एक मसौदा संहिता तैयार की।
- **वर्ष 1974 में ECI ने एक औपचारिक MCC जारी कयिा** और साथ ही इसके कार्यान्वयन की नगिरानी के लयि ज़िला स्तर पर नौकरशाही नकियाय भी स्थापति कयिा गए। **वर्ष 1977 से पूर्व MCC केवल राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का मार्गदर्शन करती थी।**
- वर्ष 1979 में नरिवाचन आयोग के संज्ञान में आया कि **सत्तारूढ़ दल** सार्वजनिक स्थानों पर एकाधिकार स्थापति करने और वजिजापन के लयि सार्वजनिक धन का उपयोग कर **सत्ता का दुरुपयोग** कर रहे हैं। **नरिवाचन आयोग ने सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों से संबधति इस मुद्दे का समाधान करने हेतु MCC में संशोधन कयिा।**
- संशोधति MCC के सात भाग शामिल थे, जनिमें से एक भाग **नरिवाचन की घोषणा के उपरांत सत्तारूढ़ दलों के व्यवहार** से संबधति था।
 - भाग I: उम्मीदवारों और पार्टयियों के लयि सामान्य अचछा व्यवहार।
 - भाग II और III: सार्वजनिक बैठकों और जुलूसों से संबधति नयिम।
 - भाग IV और V: मतदान के दिन और मतदान केंद्रों पर व्यवहार के लयि दशिया-नरिदेश।
- MCC में वर्ष 1979 के बाद से कई अवसरों पर संशोधन कयिा गया। इसमें नवीनतम संशोधन वर्ष 2014 में कयिा गया था।

MCC से संबंधित प्रमुख उपबंध:

- सामान्य आचरण:
 - कोई दल अथवा उम्मीदवार ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो भिन्न-भिन्न जातियों और समुदायों, चाहे वे धार्मिक या भाषायी हों, के बीच वदियमान मतभेद को और अधिक बगिड़े अथवा परस्पर घृणा उत्पन्न करे अथवा उनके बीच तनाव उत्पन्न करे।
 - इसी प्रकार, **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(3)** लोगों के बीच शत्रुता या घृणा को बढ़ावा देने के लिये धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के उपयोग और इसे एक राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं देती है।
 - जब राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए तो वैयक्तिक हमलों से बचते हुए उसे उनकी नीतियों और कार्यक्रम, वगित रिकॉर्ड तथा कार्य तक ही सीमा रखी जाएगी।
- बैठक और जुलूस:
 - पार्टियों को किसी भी बैठक के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को समय पर सूचित करेंगे ताकि पुलिस पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर सके।
 - यदि दो अथवा दो से अधिक उम्मीदवार एक ही मार्ग से जुलूस निकालने की योजना बनाते हैं, तो राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करने के लिये पहले से संपर्क कर लेना करना चाहिये ताकि जुलूस में आपसी टकराव न हो।
 - राजनीतिक दलों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वालों को पुतले ले जाने और जलाने की अनुमति नहीं है।
- मतदान के दिन:
 - केवल मतदाताओं और चुनाव आयोग से प्राप्त वैध पास वाले लोगों को ही मतदान केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति है।
 - मतदान केंद्रों पर सभी अधिकृत पार्टी कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बैज अथवा पहचान-पत्र दिया जाना चाहिये।
 - उनके द्वारा मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियाँ सादे (सफेद) कागज़ पर होंगी और उनमें कोई प्रतीक, उम्मीदवार का नाम अथवा दल का नाम नहीं होगा।
 - चुनाव आयोग पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगा जिनके पास कोई भी उम्मीदवार चुनाव के संचालन के संबंध में समस्याओं की रिपोर्ट कर सकता है।
- दल सत्ता में:
 - MCC द्वारा वर्ष 1979 में सत्ता में रहे दल के आचरण को वनियमिती करते हुए कुछ प्रतिबंध लागू किये। मंत्रियों के आधिकारिक दौरों को चुनाव कार्य के साथ नहीं जोड़ना चाहिये अथवा इसके लिये आधिकारिक मशीनरी का उपयोग नहीं करना चाहिये।

MCC से संबंधित मुद्दे क्या हैं?

- प्रवर्तन चुनौतियाँ: MCC का प्रवर्तन असंगत या अपर्याप्त हो सकता है, जिससे उल्लंघन हो सकता है और वैधानिक समर्थन की कमी के कारण दंडित नहीं किया जा सकता है।
 - ECI, MCC के वैधीकरण का विरोध करता है, जिसमें लगभग 45 दिनों के भीतर चुनावों को तीव्रता से पूरा करने की आवश्यकता का हवाला दिया गया है, जिससे लंबी न्यायिक प्रक्रियाओं के कारण कानूनी प्रवर्तन अव्यावहारिक हो गया है।
- अस्पष्टता: MCC के कुछ प्रावधान अस्पष्ट या व्याख्या के लिये खुले हो सकते हैं, जिससे राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के बीच भ्रम उत्पन्न हो सकता है।
- सीमा दायरा: आलोचकों का तर्क है कि MCC के दायरे को चुनावी फंडिंग, सोशल मीडिया के उपयोग तथा घृणास्पद भाषण सहित व्यापक मुद्दों को कवर करने के लिये विस्तारित किया जाना चाहिये।
- समय संबंधी मुद्दे: MCC केवल चुनाव अवधि के दौरान ही प्रभावी होता है, जिससे इस अवधि के बाद कदाचार की गुंजाइश बनी रहती है।
- शासन व्यवस्था पर प्रभाव: कुछ लोगों का तर्क है कि चुनाव अवधि के दौरान सरकारी घोषणाओं और गतिविधियों पर MCC के प्रतिबंध शासन के कामकाज में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
- सुधार की आवश्यकता: MCC की कमियों को दूर करने तथा नष्टिपक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने हेतु इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिये इसमें सुधार की मांग की जा रही है।

आगे की राह

- प्रवर्तन को सुदृढ़ बनाना: सभी राजनीतिक दलों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु MCC देश-नरिदेशों को लागू करने के लिये तंत्र को बढ़ाना।
- प्रावधानों को स्पष्ट करना: अस्पष्टता को कम करने तथा बेहतर समझ एवं अनुपालन की सुविधा के लिये MCC नयियों की स्पष्टता और विशिष्टता में सुधार करना। इस प्रकार यह एक संहिताबद्ध और व्यापक MCC की आवश्यकता है।
- नए ज़रूरतों के अनुसार दायरा बढ़ाना: डिजिटल प्रचार एवं चुनावी फंडिंग पारदर्शिता जैसे उभरते मुद्दों के समाधान के लिये MCC के कवरेज को व्यापक बनाने पर विचार करना।
- MCC को वैध बनाना: MCC को वैधानिक रूप से संस्थागत बनाने के प्रस्तावों का मूल्यांकन करना, इसे बढी हुई प्रभावशीलता और प्रवर्तनीयता के लिये वैधानिक समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है।
 - वर्ष 2013 में, कार्मिक, लोक शकियात, कानून एवं न्याय पर स्थायी समिति ने MCC को वैधानिक रूप से बाध्य करने और इसे RPA- 1951 में एकीकृत करने का प्रस्ताव रखा।
 - चुनावी सुधारों पर दनिश गोस्वामी समिति (1990) ने सुझाव दिया कि MCC की कमज़ोरी को वैधानिक समर्थन देकर और कानून के माध्यम से लागू करने योग्य बनाकर दूर किया जा सकता है।
- सार्वजनिक जागरूकता: मतदाताओं, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को MCC अनुपालन के महत्त्व एवं नष्टिपक्ष चुनाव को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका के बारे में शक्ति करने के लिये अभियान शुरू करने की आवश्यकता है।
- नरिंतर समीक्षा: उभरती चुनावी गतिशीलता और चुनौतियों से निपटने के लिये MCC के नयिमति मूल्यांकन और अनुकूलन के लिये एक रूपरेखा

स्थापति करने की आवश्यकता है।

नषिकर्ष

- आदर्श आचार संहिता (MCC) लोकतंत्र के लिये एक दिशा सूचक/मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, लेकिन घटती प्रतिबद्धता और बढ़ते उल्लंघनों के साथ चुनौतियों का सामना करती है। इसे वैध बनाने से नरिवाचन आयोग को भ्रष्टाचार से निपटने और नषिकर्ष चुनाव सुनिश्चित करने का अधिकार मलि सकता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता एवं विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिये आवश्यक है।

और पढ़ें- [भारत नरिवाचन आयोग में पारदर्शिता](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

Q. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

1. भारत का नरिवाचन आयोग पाँच-सदसयीय नकिय है।
2. संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लयि चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. नरिवाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के वभिजन/वलय से संबंधति वविद नपिताता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

??????:

Q. आदर्श आचार-संहिता के उदभव के आलोक में, भारत के नरिवाचन आयोग की भूमकि का वविचन कीजयि। (2022)